आपके डीएनए में क्या है, सारी दुनिया जान गई!!

सत्यवीर सिंह

'मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, भारत, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र होने पर बहुत दिनों से अभिमान करता आया है, लेकिन कई मानवाधिकार समूह हैं, जिनका कहना है कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव तथा आलोचकों का मुंह बंद कर रही है। वाइट हाउस के पूर्वी कमरे में, जहां आज आप खड़े हैं, वहां दुनिया के कितने ही नेताओं ने, लोकतंत्र को बचाने की क़समें खाई हैं। अपने देश में, बोलने की आज़ादी का सम्मान करने, मुस्लिम एवं दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की दशा सुधारने के लिए, आपकी सरकार कौन से क़दम उठाने की इच्छुक है? 'वाल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीक़ी ने 22 जून को मोदी से ये सवाल पूछा।

सकपकाए प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले दो घूंट पानी पिया, और ये जवाब दिया; 'मैं हैरान हूं कि आप इस टिप्पणी को दूसरों के नाम रख रही हैं। लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है। ये हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वजों ने इसे संविधान में लिख रखा है। अगर आप लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं तो जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भारत में लोकतंत्र अच्छी तरह काम कर रहा है और सरकार की विभिन्न लाभ-योजनाओं तक, सभी धर्म, सम्प्रदायों को मानने वालों की एक समान पहुंच है।'

ये सवाल-जवाब, अगर किसी परीक्षा में हुआ होता, तो कॉपी जांचने वाला कॉपी को दूर फेंक कर, जीरो नंबर देता। किसी भी सवाल का जवाब वह होना चाहिए जो पूछा गया है न कि वह जो परीक्षार्थी ने रटा हुआ है। नागरिक अधिकारों को बेरहमी से कुचलने, योजनाबद्ध तरीक़े से जनवाद के सभी इदारों को अन्दर से खोखला कर उनका सत्यानाश करने, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव मात्र नहीं, बल्कि समूचे मुस्लिम समुदाय को 'आतंकी, जेहादी और देशद्रोही' बताकर, शत्रु जैसा व्यवहार करने, जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वालों को प्रताड़ित करने और उनके पीछे ईडी, सीबीआई को लगा देने की, देश की मौजूदा क्रूर हक़ीक़त को, सबरीना सिद्दीकी ने जितने सहज और स्वीकार्य ढंग से रखा, उससे बेहतर संभव नहीं था। देश की मौजूदा हुकूमत और उसके 'कुनबे' की शिराओं में इस वक़्त क्या बह रहा है और उनके डीएनए में असलियत में क्या है, इस एक सवाल ने, नंगा करके रख दिया!!

मुद्दे को और गरमाने के लिए, बराक ओबामा भी मैदान में कूद पड़े। मानो, भारत में, लोकतंत्र पर हो रहे, मोदी सरकार के हमले से वे विचलित हो उठे हों! ओबामा, बाईडेन और अमेरिका खुद लोकतंत्र के कितने बड़े चैंपियन हैं, चर्चा उस पर भी होगी, लेकिन पहले, सीएनएन को दिए उनके इंटरव्यू में उनका वह बयान, जिसने देश की फासिस्ट टोली को काम पर लगा दिया है; 'अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, बात करने का अवसर मिला होता, तो मेरे तर्क का लब्बोलुआब ये होता कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की हिफ़ाज़त नहीं करेंगे, तो इस बात की आशंका काफ़ी प्रबल है कि देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा... इसका दूरगामी असर अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक हिन्दुओं के भविष्य पर भी पड़ेगा।'

'सबरीना सिद्दीकी' और 'बराक हुसैन ओबामा' नामों से देश में बौराए फिर रहे फासिस्ट टोले को, वे दो 'निर्णायक शब्द' (कीवर्ड) हाथ लग गए, जो उन्हें चाहिए थे। दरअसल, फ़ासिस्ट आतंकी टोलियों और भाजपा आईटी सेल पर लगे भाड़े के ट्रोल को, इतना ही सिखाया गया है कि वे सभी व्यक्ति, जिनके नाम उर्दू में है, मुस्लिम हैं, मतलब आतंकी, जेहादी हैं, मतलब देशद्रोही हैं, उन पर टूट पड़ना है। जो जितनी ज्यादा और जितनी गंदी गालियां देगा, वह हुकूमत का उतना ही वफ़ादार समझा जाएगा, उतना ही देशभक्त कहलाएगा, तरक्की और भुगतान पाएगा। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा, जो चंद वर्ष पहले तक कांग्रेसी हुआ करता था और भाजपा को फिरकापरस्त बताकर, कांग्रेसी हमलावर टोली में सबसे आगे रहा करता था, आज, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में मिली क़ामयाबी के बाद से, फ़ासिस्ट मोदी सरकार का सबसे वफ़ादार हमलावर है। वह, न सिर्फ असम का मुख्यमंत्री है बल्कि समूचे उत्तर-पूर्वी राज्यों का 'भाग्यविधाता' है, जिसका खामियाजा, आज मणिपुर भुगत रहा है। मोदी अमेरिका में ही थे कि उसके इस ट्वीट ने साबित कर दिया कि मोदी के डीएनए में क्या है? ''भारत में ही कई हुसैन ओबामा हैं। वाशिंगटन जाने से पहले हमें उनका बंदोबस्त करने की प्रथामिक्ताएं तय करनी होंगी। असम पुलिस हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेगी।''

'अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है', प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का यह कालजयी कथन, आजकल हर रोज़ याद आता है। कुछ लोग जो फ़ासिस्ट टोले की फ़ितरत नहीं जानते, सोच रहे थे कि असम का मुख्यमंत्री, इस बार, अपनी सीमा लांघ गया और वह अपने 'टिटियाने' को वापस लेगा। वैसा नहीं होना था, यह तो दरअसल एक इशारा था। उसके बाद भाजपा की आईटी सेल के नाम पर चल रही, झूठ और फ़र्ज़ी खबरों की देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मुखिया और छोटे-मझोले-बड़े सभी श्रेणी के भक्त शुरू हो गए। अमेरिकी मुसलमानों को सबक सिखाने की ये मुहिम भी केंद्र के, महाबली हाई कमांड द्वारा संचालित है, तब समझ आया, जब हेमंत बिस्व सरमा बोला कि वह अपने टिटियाने पर क़ायम है और वित्त मंत्री भी, बराक ओबामा पर पिल पड़ीं।

युद्ध शास्त्र का ये पैंतरा आजकल सब सीख गए हैं, 'आक्रामकता ही सबसे कारगर बचाव है'. वित्त मंत्री अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी सरकार के कारनामे, उससे कहीं संगीन हैं, जो आरोप उन पर, अमेरिका में लगे हैं। मोदी सरकार की बदकिस्मती, कि सारे मीडिया को पालतू बनाकर भी, सच्चाई को क़ैद करना आज मुमकिन नहीं रहा। सोशल मीडिया को कैसे रोकेंगे? उसे रोकने के लिए, इन्टरनेट को ठप्प करना पड़ेगा, लेकिन इन्टरनेट के बगैर आजकल परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई वित्तीय लेन-देन संभव नहीं। हर व्यक्ति, हर वक़्त ऑनलाइन है। कश्मीर का तजुर्बा हमारे सामने है; इन्टरनेट चालू करना ही पड़ा। बराक ओबामा के कार्यकाल में सीरिया, लीबिया, इराक़, यमन, अफ़गानिस्तान और फिलिस्तीन 6 मुस्लिम देशों पर, कितनी भयानक बमबारी हुई, 26,000 बम गिराए गए, कितना हाहाकार मचा, ये बात ओबामा को याद दिलाई गई, लेकिन धूर्तता के साथ। अमेरिका का नाम नहीं लिया, मानो बमबारी का फैसला, अमेरिकी सरकार का न होकर, ओबामा का निजी फैसला हो! अमेरिकी आकाओं को ना-खुश नहीं किया जा सकता ना!!

मोदी के स्वागत में अमेरिकनों ने लगाया पोस्टर

इंडिया-अमेरिका, दोनों का डीएनए एक है

ओबामा और बाईडेन की अंग्रेजी बोलने की नफ़ासत, मोदी से कहीं बढ़िया है; ये बात सही है। ये बात, लेकिन, मायने नहीं रखती। ट्रम्प भी तो ऐसा ही डफर है!! मायने ये रखता है कि मानवाधिकारों, जातिगत और नस्लगत उत्पीड़न-अत्याचार में इंडिया और अमेरिका का क्या रिकॉर्ड है? दोनों देशों के बीच हुए, व्यवसायिक सौदे किसके हित में हैं, उनके क्या परिणाम होंगे? इन सब शाही स्वागत-सत्कारों, अनर्गल लफ्फाज़ियों को, मेहनतकश अवाम, कमेरा वर्ग किस तरह समझे?

दुनियाभर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन नहीं जानता? कौन सा अपराध है जो अमेरिकी शासकों ने नहीं किया? अमेरिका, अपनी दैत्याकार सैन्य-शक्ति और खूंख्वार खुफ़िया एजेंसी, सीआईए के ज़रिए, अब तक कुल 105 सार्वभौम देशों की सत्ताओं का तख्ता पलटकर, अपने पिट्ठुओं को सत्ता में बैठा चुका है। समस्त लैटिन अमेरिका उसकी शिकारगाह है।

दुनिया भर के अनगिनत कम्युनिस्ट आन्दोलनों को, उसकी भाड़े की सेना ने कुचलकर लहुलुहान किया है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के हाथ ही नहीं, सारे शरीर, करोड़ों बेक़सूरों के खून से रंगे है। इराक में विनाशकारी हथियारों के नाम पर कितना झूठ, कितना घिनौना खूनी प्रपंच, लोकतंत्र के स्वयं-घोषित, इस ठेकेदार अमेरिका ने रचे और खाड़ी के सबसे प्रगतिशील देश को तबाह कर डाला। ओसामा को पैदा किया और अफ़गानिस्तान में सालों-साल खूनी खेल खेला और अंत में जब उसके वित्तीय हित सधने बंद हो गए, तो दुनिया की सबसे कट्टर, असभ्य तालिबानी सरकार को सत्ता सौंपकर, बेगैरती से दुम दबाकर भागने वाला, यही अमेरिका था। जंग न हो, तो रक्त-पिपासू अमेरिकी वित्तीय सरमाएदार भूखे मरने लगते है। उन्हें हर वक़्त जंग चाहिए। युक्रेन में, अमेरिका ने, ना सिर्फ़ युद्ध भड़काया बल्कि वहां शांति प्रस्थापित होने के हर प्रस्ताव को अंजाम तक पहुंचने से रोका।

निर्मला सीतारमण

जो बाईडन

अमेरिका को दुनिया का लठैत और लोकतंत्र का उपदेशक, किसने चुना है? दूर का इतिहास छोडिए, इसी अमेरिका के सबसे ताक़तवर अख़बार वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार, खशोगी को तुर्की के दूतावास में, सऊदी कसाई, मोहम्मद बिन सलमान के भाड़े के टट्टुओं ने, इस तरह क़त्ल किया जिसकी मिसाल नहीं. लोकतंत्र का क़त्ल करने की, इससे जघन्य मिसाल नहीं मिलेगी. अमेरिकी समाज और मीडिया, उस सलमान को, गिरफ्तार कर सज़ा दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरा. लेकिन, क्या हुआ? दुनिया से अपना रक्तरंजित मुंह छिपाने वाले, उसी खूनी हत्यारे से, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, गलबहियां करके आया. वियतनाम में अमेरिकी अपराध क्या भुलाए जाने लायक़ हैं? अकेले युक्रेन युद्ध से, अमेरिका के जंगखोर धन-पशुओं का पेट नहीं भर रहा, अब हमारे पड़ौस में, ताईवान को युद्ध के लिए भड़काया, उकसाया जा रहा है। ये है, लोकतंत्र के अमेरिकी पाठ की हकीक़त। जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 'डेमोक्रेसी' शब्द मुंह से निकाले, सारी दुनिया के अमनपसंद अवाम ने एक सुर में बोलना चाहिए; 'लानत है'!!

'डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, डेमोक्रेसी हमारी नसों में बहती है', प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका की धरती पर दिया ये बयान, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इतना सफ़ेद झूठ लोग कैसे बोल लेते हैं, सोच कर घिन आती है।

डीएनए और नसों में क्या है, वह तो पूरी दुनिया जान गई उस असलियत को बार-बार दोहरा कर क्यों वक़्त बर्बाद किया जाए? देश को यह जानना ज़रूरी है कि अभूतपूर्व बेरोज़गारी, भयानक कंगाली और मंहगाई के पहाड़ तले कराहते देशवासियों के लिए, मोदी जी अमेरिका से क्या सौगात लेकर आए? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा ग़रीब रहते हैं। साथ ही, भारत, दुनिया भर में, हथियारों और खुफ़िया तंत्र का सबसे बड़ा ख़रीदार है। भारत-अमेरिकी हथियार ख़रीद के इस सौदे से पहले के, 5 सालों में भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन से कुल 1.9 लाख करोड़ के हथियार और गोला-बारूद, अत्याधुनिक रायफलें, निगरानी के उपकरणों के कुल 264 ख़रीद सौदे किए हैं। ये वह माल है जो, देश में हो रहे उत्पादन के अतिरिक्त विदेशों से ख़रीदा गया है। ये जानकारी रक्षा उप-मंत्री अजय भट्ट ने फरवरी महीने में लोकसभा को दी। वर्षवार ब्यौरा इस तरह है; रु 30,677 करोड़- 2017 -18,

शेष पेज सात पर

प्री-मानसून बारिश में शहर डूबा अधिकारी कब होंगे पानी-पानी

नालों की सफाई का अता-पता नहीं, थोड़ी बरसात में ही सड़कों पर हो जाता है जलभराव

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बारिश के पानी की निकासी और नालों की सफाई के प्रशासन व नगर निगम के दावों की पोल रविवार को हुई प्री मानसून की थोड़ी देर की बरसात ने खोल दी। शहर हो या हूडा के सेक्टर या स्मार्ट सिटी का इलाका, हर जगह सड़कों पर जलभराव हुआ, यहां तक कि नेशनल हाइवे की सर्विस लेन भी डूबी हुई थीं। जलभराव का खामियाजा शहर वासियों को, वाहन चालकों खासकर दो पहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ा।

जिला उपायुक्त से लेकर निगमायुक्त, हूडा प्रशासक सब ही बारिश आने से पहले नालों की सफाई का राग अलापते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपये कागजों पर ही खर्च कर दिए जाते हैं जबकि नालों की हालत हल्की सी बारिश आते ही पहले से बदतर हो जाती है। अधिकारी हर बैठक में जोर जोर से बारिश के पानी की निकासी का मजबूत प्रबंध किए जाने के दावे करते हैं इसके उलट बरसात होते ही पानी नालों में बहने के बजाय उफन कर सड़कों पर बहते देखा जा सकता है। रविवार को हुई बारिश में भी पूरे शहर के यही हालात थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री खट्टर के हूडा कन्वेंशन हॉल जाने वाली सड़क पर भी जलभराव हो गया। मामला मुख्यमंत्री का था तो प्रशासन ने तुरंत सुपर सकर मशीन मंगवा दी लेकिन सीएम का काफिला आने के बाद तक पूरा पानी नहीं निकाला जा सका लेकिन आम आदमी के लिए प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं।

सेक्टर चार गुड़गांव कैनाल झुग्गियों में रहने वाला बुलबुल सेक्टर 14 में पेड़ के नीचे कुर्सी और शीशा रख कर लोगों के दाढ़ी-बाल काटने का काम करता है। रविवार को वह सुबह आठ बजे दुकान जाने के लिए घर से निकला तो सड़क पर जगह-जगह इतना जलभराव था कि उसकी साइकिल का आधे से अधिक पहिया डूब रहा था। जाहिर ऐसे में वह साइकिल लेकर पैदल ही पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हुआ। इस दौरान कई बार गड्ढों में उलझ कर गिरते गिरते भी बचा। सड़कें तो पानी से भर ही जाती हैं। परेशान बुलबुल ने बताया कि दुकानदारी तो बर्बाद हुई ही सड़क पर पानी भरा होने से घंटो इंतजार करना पड़ा, जब पानी उतरा तब दुकान पहुंच सका। बुलबुल की तरह ही अनेक ई रिक्शा, रेहड़ी वालों को सड़क पर हुए जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पानी जाने से कई ई रिक्शा खराब हुए तो रेहड़ी वालों का सामान भीग कर खराब हुआ। इन गरीबों का कहना था कि यदि बारिश के पानी की निकासी का उचित इंतजाम होता, नाले साफ होते तो शायद यह नुकसान न होता। प्रशासन को इन गरीबों की समस्या से क्या, उसे तो हर साल नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये डुबाने हैं जिसका परिणाम आम आदमी को उसके घर में पानी घुसने, बाढ़ जैसे हालात में गुजर-बसर कर भुगतना पड़ता है। निलर्ज्ज हो चुके अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।